नईदुनिया

फिर एक बार अमेरिकी दूतावास पर निशाना, आधे घंटे तक चली गोलियां, लेबनानी सैनिकों ने एक को पकड़ा

बेरूत ।

लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर हमले का प्रयास करने वाले बंदूकधारी को लेबनानी सैनिकों ने पकड़ लिया। इस घटना लेबनान में जारी तनाव के बीच घटी। दरअसल, पिछले एक महीने से सीमावर्ती क्षेत्रों में हिजबुल्ला आतंकी और इजराइली सैनिकों के बीच झड़प जारी है। लेबनानी सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि सैनिकों ने एक हमलावर को गोली मार दी। उन्होंने हमलावर की पहचान सीरिया के नागरिक के तौर पर की है। गली लगने के बाद हमलावर को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, इस घटना के बाद हमलावर के हमले का उद्देश्य क्या था, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेबनानी मीडिया ने एक तस्वीर जारी की, जिसमें हमलावर खून से लथपथ हमलावर एक ने काली रंग की बनियान पहन रखी थी। उसके बनियान में इस्लामिक स्टेट लिखा हुआ था। अमेरिकी दूतावास के बाहर आधे घंटे तक चली गोलीबारी लेबनानी मीडिया ने बताया कि अमेरिकी दूतावास के बाहर करीब आधे घंटे तक गोलीबारी हुई। लेबनानी सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि चार हमलावर थे, उनमें से एक बाकी के हमलावरों को घटनास्थल पर लेकर आया था। उन्होंने कहा कि एक हमलावर की मौत हो गई, दूसरा मौके से भाग निकला। तीसरा घायल हो और चौथे को हिरासत में ले लिया गया था। अमेरिकी दूतावास ने इस हमले के बाद प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि इस हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्री और आर्मी कमांडर के साथ बैठक के बाद उन्हें स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। फिलहाल स्थिति स्थिर है और इस मामले की जांच जारी है। लेबनान की सेना ने बताया कि हमले के बाद सैन्यकर्मियों को दूतावास के बाहर तैनात किया गया है। इससे पहले भी हो चुका है अमेरिकी दूतावास पर हमला बता दें कि 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया था, जिसमें 63 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने इस हमले के लिए लेबनानी आतंकी ग्रुप हिजबुल्ला को जिम्मेदार ठहराया था। इस हमले के बाद अमेरिकी दूतावास को मध्य बेरूत से औकार में स्थानांतरित कर दिया गया था।

न्यूज ब्रीफ

मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने पीएम मोदी को दी आम चुनाव में जीत की बधाई, लिखा- साथ मिलकर काम करेंगे

माले । सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा और भाजपा नीत एनडीए को लगातार तीसरी बार आम चुनाव 2024 में जीत की बधाई। मैं दोनों देशों के साझा हितों, समृद्धि और स्थिरता के लिए साथ मिलकर काम करने की तरफ देख रहा हूं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने 2024 के आम चुनाव में एनडीए की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। मालदीव के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि वह पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करेंगे। भारत के आम चुनाव के नतीजे जारी कर दिए गए, जिनमें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने जीत हासिल की है। इस जीत को लेकर दुनियाभर के नेताओं से भारत और पीएम मोदी को बधाई दी जा रही है। मालदीव के राष्ट्रपति ने दी बधाई सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा और भाजपा नीत एनडीए को लगातार तीसरी बार आम चुनाव 2024 में जीत की बधाई। मैं दोनों देशों के साझा हितों, समृद्धि और स्थिरता के लिए साथ मिलकर काम करने की तरफ देख रहा हूं। गौरतलब है कि मालदीव और भारत के रिश्ते बीते दिनों तल्खी के दौर से गुजरे और मोहम्मद मुइज्जू को चीन समर्थक और भारत विरोधी नेता माना जाता है। इटली की पीएम समेत दुनियाभर के नेताओं ने दी जीत की बधाई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जीत की बधाई दी है। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में मेलोनी ने लिखा कि नई चुनावी जीत और अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं। निश्चित है कि हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करेंगे और दोनों देशों के लोगों को भलाई से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत की बधाई। वो भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं, मैं उनके साथ मिलकर काम करने की तरफ देख रहा हूं, जिससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो सकें। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे ने भी पीएम मोदी को बधाई दी और लिखा कि भाजपा नीत एनडीए को जीत की बधाई। भारतीय लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि में के प्रति अपना विश्वास दिखाया। सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका, भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर है।

लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अमेरिका ने भारतीयों को दी बधाई विदेश ताकतों के दखल के आरोपों का किया खंडन

वॉशिंगटन । लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और देश में एक बार फिर भाजपा नीत एनडीए की सरकार बनने वाली है। जारी रुझानों के अनुसार, इंडी गठबंधन भी बहुमत से ज्यादा दूर नहीं था। लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने लोकसभा चुनाव में सफलतापुर्वक भाग लेने और इसे खत्म कराने में भारत सरकार की सराहना की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इस दौरान विदेश ताकतों के दखल के आरोपों का किया खंडन भी किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। भले ही तीन हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आखिरकार भाजपा नीत एनडीए को बहुमत मिल ही गया। अमेरिका ने की भारत सरकार की सराहना चुनाव आयोग ने लोकसभा की 543 सीटों के नतीजे जारी किए, जिसमें भाजपा ने 240 सीटों पर और कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत हासिल की। नतीजे जारी होने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भारत सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा, अमेरिका की तरफ से लोकसभा चुनाव में सफलतापुर्वक भाग लेने और इसे खत्म कराने के लिए हम भारत सरकार और मतदाताओं का धन्यवाद करते हैं। हम अंतिम परिणाम देखने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मिलर ने कहा, मैं इस चुनाव में विजेताओं और हारने वालों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूं, जैसा कि हमारे मामलों में अक्सर होता है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है और पिछले छह हफ्तों में हमने जो देखा वह लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा अभ्यास है। क्योंकि भारत के लोग मतदान के लिए आए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका सहित पश्चिमी देशों द्वारा भारतीय चुनावों में बाहरी प्रभाव की रिपोर्टों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा, हम हमेशा अपने विचार विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगे। हम अपने विचार निजी तौर पर विदेशी सरकारों के साथ साझा करते हैं।

ताइवान के आसपास फिर दिखे चीनी लड़ाकू विमान, दोनों देशों में बढ़ा तनाव

ताइपे ।

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि करीब 26 चीनी लड़ाकू विमान और 10 युद्धपोत ताइवान की सीमा के आसपास दिखाई दिए। ताइवान मीडिया के अनुसार, 26 लड़ाकू विमानों में से 19 चीन और ताइवान की सीमा बांटने वाली मीडियन लाइन को भी क्रॉस कर गए। चीन की इस हरकत को उकसावे वाली कार्रवाई बताया जा रहा है।

चीन और ताइवान के बीच बढ़ा तनाव

ताइवान के मीडिया ने बताया कि चीनी लड़ाकू विमानों के जवाब में ताइवान ने भी अपने लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों को भेजा। साथ ही तटीय इलाकों पर अपने मिसाइल सिस्टम को भी सक्रिय कर दिया, ताकि चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जा सके। गौरतलब है कि ताइवान में बीती 20 मई को ही नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। नई सरकार बनने के बाद से ही चीन का रुख आक्रामक है और उसके लड़ाकू विमान और युद्धपोत लगातार ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं।

चीन की इस कार्रवाई को उकसावे के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ताइवान की आजादी की बात अपने भाषण में कही, जिसने चीन को नाराज कर दिया है। हाल ही में चीन की सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी कर्नल वू कियान ने कहा था कि ताइवान की आजादी का मतलब सिर्फ युद्ध है और ताइवान में अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

चीन की सेना लगातार ताइवान पर बना रही दबाव

चीनी सेना के अधिकारी ने कहा कि चीन का एकीकरण ऐसी घटना है, जिसे टाला नहीं जा सकता। उल्लेखनीय है कि चीन, ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और यही वजह है कि वह ताइवान की आजादी का विरोध करता है। ताइवान में नई सरकार के गठन के बाद से ही चीन की सेना के लड़ाकू विमान आए दिन ताइवान की सीमा के आसपास मंडराते नजर आ जाते हैं। ताजा घटना को भी उसी दबाव बनाने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

गाजा पर इजराइली हमले तेज 19 की जान गई; फलस्तीन को मान्यता देने वाले देशों स्लोवेनिया भी शामिल

गाजा। मध्य और दक्षिणी गाजा में हवाई हमलों और गोलाबारी से लगभग 19 लोगों की मौत हो गई है। करीब आठ महीनों से जारी लड़ाई को बंद करने की अंतरराष्ट्रीय अपील के बाद इजराइल ने हमले और तेज कर दिए हैं। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक अल- बुरीज और अल-मगाजी शरणार्थी शिविरों और मध्य गाजा के दीर-अल-बलाह शहर पर इजराइली हमलों में 17 लोग मारे गए। वहीं रफा में मानवीय मदद पहुंचा रहे 2 पुलिसकर्मी भी हमले में मारे गए। स्लोवेनिया ने भी फलस्तीन को देश के तौर पर मान्याता दी स्लोवेनिया फलस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने वाला नया यूरोपीय देश बन गया है। इसके पहले स्पेन, आयरलैंड और नार्वे फलस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। स्लोवेनिया के ऐसा करने का मकसद इजराइल के युद्ध बंद करने के लिए दबाव बनाना है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के गाजा में हमला करने के बाद से इजराइल ने आक्रामक रुख अपना रखा है। 'जब तक इजराइल की सेना वापस नहीं जाती सीजफायर नहीं रुकेगा' हमास ने बयान देते हुए कहा कि जब इजराइल स्पष्ट रूप से युद्ध विराम का वादा नहीं करता और अपनी सेनाओं को वापस नहीं ले जाता, तब लड़ाई नहीं रुकेगी। हमास का बयान तब आया है, जब कतर ने भी यहूदी देश से समझौता करने को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है।

जो बाइडन के बेटे हंटर की बढ़ीं मुश्किलें बंदूक खरीदने के मामले में अभियोजन पक्ष में कहा- उन्हें नशे की लत

वॉशिंगटन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अभियोजन पक्ष ने बंदूक मामले में जूरी सदस्यों के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति बाइडन का बेटा एक नशे का आदी था। उसने रिवॉल्वर पाने के लिए कागजी कार्रवाई पर झूठ बोला था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता है। डेलावेयर की संघीय अदालत में जूरी ने गवाह से पहले अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों के बयान सुने। एफबीआई एजेंट को भी बुलाया गया।

बचाव पक्ष के वकील एब्बे लोवेल ने जूरी से कहा कि ट्रायल में पेश किए सबूतों से पता चलेगा कि 54 वर्षीय हंटर बाइडन जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन नहीं किया। यह पहली बार ऐसा हुआ जब किसी वर्तमान राष्ट्रपति के बेटे पर मुकदमा चल रहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बन चुके हैं, जिन्हें अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग के वकील डेरेक हाइंस ने जूरी सदस्यों को अक्तूबर 2018 की घटनाओं के बारे में बताया था, जब हंटर बाइडन ने बंदुक खरीदते समय बैकग्राउंड की जांच के दौरान ड्रग्स के उपयोग को लेकर झूठ बोला था। हाइंस ने कहा, यह गैरकानूनी था, क्योंकि वह नशे का आदी था। हंटर बाइडन ने तीन आरोपों में दोषी न होने की बात कही थी, जिसमें कोल्ट कोबरा 38-कैलिबर रिवॉल्वर खरीदने के दौरान अवैध दवाओं के उपयोग का खुलासा न करने और अक्तूबर 2018 में 11 दिनों के लिए अवैध रूप से हथियार रखने का आरोप शामिल हैं। बचाव पक्ष के वकील ने जूरी से सबूतों को ध्यान से सुनने की अपील की। उन्होंने बताया कि बंदूक खरीदने के दौरान एक फॉर्म में हंटर बाइडन से यह पूछा गया था कि वह र्तमान में नशे के आदी है या नहीं। उनसे यह नहीं पूछा गया कि उन्होंने कभी पहले इसका इस्तेमाल किया था नहीं। क्या है पूरा मामला पिछले साल अदालत ने माना था कि हंटर ने हथियार खरीदने के लिए कई बार झूठ बोला है। उन पर अक्तूबर 2018 में बंदूक खरीदने के दौरान अपनी नशे की लत को लेकर झूठ बोलने का भी आरोप है। कहा गया था कि हंटर ने जब अक्तूबर 2018 में डेलावेयर के कॉल्ट कोबरा स्पेशल स्टोर से बंदूक खरीदी थी।

अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर प्रवासियों को नहीं मिलेगी शरण, राष्ट्रपति बाइडन ने जारी किया आदेश

वॉशिंगटन।

अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन ने अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर शरण मांगने वाले प्रवासियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस में द्विदलीसय सीमा सुरक्षा समझौते के विफल होने के बाद डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति कई महीनों से इस पर विचार कर रहे हैं। दरअसल कई सारे रिपब्लिकन सांसदों ने संभावित रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर खारिज कर दिया था। जो बाइडन का यह आदेश दक्षिणी सीमा पर अतिक्रमण, प्रवासियों के शरण पर रोक लगाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों की मानें तो यह आदेश तब लागू होगा जब प्रवेश में बंदरगाहों के बीच सीमा मुठभेड़ की संख्या प्रतिदिन 2500 हो जाएगी। बता दें कि दैनिक औसत लगभग इससे अधिक ही है। इसलिए यह आदेश तुरंत लागू किया जाएगा। बता दें कि यह प्रतिबंध दो सप्ताह तक प्रभावी रहेगा। जब तक कि प्रवेश के बंदरगाहों के बीच प्रतिदिन मुठभेड़ों की संख्या सात दिवसीय औसत के तहत 1,500 या उससे कम न हो जाए। आदेश लागू होते ही जो भी प्रवासी सीमा पर पहुंचेंगे, लेकिन देश वापस लौटने का डर नहीं होगा, उन्हें कुछ ही दिनों या घंटों में संयुक्त राज्य अमेरिका से वापस भेज दिया जाएगा। इन प्रवासियों पर अगले पांच साल तक प्रतिबंध और संभावित आपराधिक मुकदमा भी सजा के तौर पर किया जा सकता है। प्रतिबंध के दौरान हर शरणार्थी की जांच अमेरिका शरण अधिकारी द्वारा की जाएगी। जांच में सफल होने के बाद यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सहित मानवीय सुरक्षा के अधिक सीमित रूपों का पालन कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के आदेश को समझाते हुए प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि यह निर्देश ऐसे समय आया है जब दिसंबर से सीमा पर मिलने वाले प्रवासियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है।

फलस्तीनियों की हालत भयावह, बच्चों को नहीं मिल रहा तीन दिन में भी एक बार का खाना, ऑक्सफैम की चेतावनी

पेरिस ।

गाजा में युद्ध के कारण विस्थापित हुए फलस्तीनी भयावह परिस्थितियों में रह रहे हैं। बच्चे कभी-कभी पूरे दिन बिना भोजन के रह रहे हैं और हजारों लोग एक ही शौचालय साझा कर रहे हैं। ऑक्सफैम ने यह चेतावनी दी। हाल के हफ्तों में मिस्र की सीमा के पास गाजा पट्टी के दक्षिणी क्षेत्र राफा में इजराइली बलों ने बमबारी की की है। जिसने उन लोगों को फिर से विस्थापित कर दिया है, जो गाजा के अन्य हिस्सों से जान बचाकर यहां पहुंचे थे।

संयुक्त राष्ट्र की फलस्तीनी शरणार्थी एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए के मुताबिक, दस लाख से ज्यादा लोग राफा से भागकर अन्य क्षेत्रों की ओर चले गए हैं। ऑक्सफैम ने कहा कि

गाजा की दो-तिहाई से ज्यादा आबादी घिरे हुए क्षेत्र के पांचवें हिस्से से भी बहुत कम होने का अनुमान है।

एजेंसी ने कहा, इजराइल के हमलों के बावजूद पलायन कर रहे लोगों को पूरी मदद प्रदान की जाएगी। गाजा का अधिकांश हिस्सा मानवीय मदद से वंचित हो गया है, जो अकाल का सामना कर रहा है। इसने आगे कहा, सहायता एजेंसी द्वारा मई में किए गए एक खाद्य सर्वेक्षण में पाया गया कि सर्वेक्षण से पहले 85 फीसदी बच्चों ने तीन दिन में एक बार से भी पूरे दिन खाना नहीं खाया था।

ऑक्सफैम ने संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों का हवाला देते हए कहा कि जब से इजराइली बलों ने छह मई को राफा पर अपना जमीनी अभियान शुरू किया है, तबसे हर दिन औसतन आठ सहायता ट्रकों ने प्रवेश किया। ऑक्सफैम के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के निदेशक सैली अबी खलील ने कहा, जब तक अकला की घोषणा की जाती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पिछले हफ्ते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्होंने गाजा में भुखमरी के आरोपों को खारिज किया औक कहा कि अकाल को रोकने के लिए सबकुछ किया गया। उन्होंने कहा कि गाजा के लोग एक दिन 3,200 कैलोरी खा रहे हैं या दैनिक जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं।

दोषसिद्धी के बाद पहली बार ट्रंप की चुनावी परीक्षा, बहुत कुछ है दांव पर

वॉशिंगटन।

एडल्ट स्टार के साथ अपने संबंध छिपाने के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्राइमरी चुनाव में शामिल होंगे। यह प्राइमरी चुनाव का आखिरी चरण है और ट्रंप के दोषी ठहराए जाने के बाद इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा है। अमेरिकी समय के अनुसार, मोंटाना, न्यूजर्सी और न्यू मैक्सिको में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी चुनाव होने हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के भी इन राज्यों के साथ ही वॉशिंगटन डीसी और दक्षिण डेकोटा में प्राइमरी चुनाव होने हैं।

प्राइमरी चुनाव में बहुत कुछ दांव पर रिपब्लिकन पार्टी के वॉशिंगटन डीसी में मार्च में ही प्राइमरी चुनाव हो चुके हैं, जबकि दक्षिण डेकोटा में रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी चुनाव रद्द हो गए थे। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडन इन प्राइमरी चुनाव में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ट्रंप और बाइडन के इन चुनाव में आसानी से जीतने की उम्मीद है क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये ही दोनों मुख्य उम्मीदवार बचे हैं। हालांकि इसके बावजूद इन चुनाव में काफी कुछ दांव पर है।

दरअसल अगर रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का अंतर उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि शायद जघन्य मामले में दोषी पाए जाने के बाद लोग ट्रंप को वोट देने से हिचक रहे हैं। साथ ही राष्ट्रपति पद की दावेदार रहीं निक्की हेली ने अपनी उम्मीदवार वापस लेने के बाद बीते दिनों कहा था कि वह डोनाल्ड ट्रंप को वोट करेंगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि निक्की हेली के समर्थक भी ट्रंप का समर्थन कर सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के आसार बढ़ जाएंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीनन ये ट्रंप के लिए चिंता की बात हो सकती है। ये प्राइमरी चुनाव राष्ट्रपति जो बाइडन के लिए भी अग्निपरीक्षा के समान हैं। दरअसल इजराइल हमास युद्ध में अपने स्टैंड को लेकर बाइडन आलोचकों के निशाने पर हैं। ऐसे में प्राइमरी चुनाव के नतीजों से तय हो जाएगा कि आम लोग इसे लेकर क्या सोचते हैं।

ट्रंप के वकील ने कोर्ट से की अपील

डोनाल्ड ट्रम्प के वकील ने न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश से उस आदेश को हटाने की मांग की है, जिसके तहत पूर्व राष्ट्रपति को आपराधिक मामले से जुड़े गवाहों, ज्यूरी सदस्यों और अन्य लोगों के बारे में टिप्पणी करने से रोक दिया गया था। ट्रंप पर सेक्स स्कैंडल को छिपाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का दोषी ठहराया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ट्रंप पर मामले से जुड़े गवाहों, ज्यूरी सदस्यों और अन्य लोगों के बारे में टिप्पणी करने से रोक लगा दी गई थी। ट्रंप के वकील ने कहा कि अब मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। ऐसे में इस आदेश के लागू रहने का कोई मतलब नहीं है। ट्रंप के वकील ने कहा कि मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब 27 जून को राष्ट्रपति चुनाव की पहली बहस होने वाली है। ऐसे में ट्रंप पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की ताकि वह खुलकर अपना पक्ष रख सकें।